माननीय आर. पी. सेठी और सत पाल, जे.जे. के समक्ष

हिंदू एजुकेशन सोसायटी (रजि.), रोहतक और अन्य, - अपीलकर्ता।

बनाम

श्याम सुंदर पसरीजा और अन्य, -प्रतिवादी।

एल.पी.ए. 1993 का क्रमांक 771,

15 नवम्बर 1994।

लेटर पेटेंट अपील खंड एक्स - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 11 - हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 - धारा 7 - रचनात्मक पूर्वन्याय का सिद्धांत।

अभिनिर्णीत, कि हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया, द्वारा की गई दलीलों पर उत्सुकता से विचार किया है। जैसा कि पहले कहा गया है, निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ ने अपने आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1985 द्वारा, प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करने का जुर्माना लगाने की सीमा तक प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संशोधन में उक्त आदेश को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अपने आदेश, दिनांक 6 अप्रैल, 1987 द्वारा रद्द कर दिया था, और प्रतिवादी को सभी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद, प्रबंधन ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा 6 अप्रैल, 1987 को पारित उपरोक्त आदेश को 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 में चुनौती दी, जो इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी, - 1 सितंबर, 1987 के फैसले के तहत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा पारित 6 अप्रैल, 1987 के आदेश को रद्द कर दिया गया था और निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1985 को बहाल कर दिया गया। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति 1987 के सी.डब्ल्यू.पी संख्या 2845 में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा था। 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2845 में दिए गए फैसले को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था, - 1988 के एलपीए नंबर 25 में 17 जनवरी, 1990 के फैसले के जरिए। उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से यह तर्क दिया गया कि निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सही ढंग से रद्द कर दिया था। 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2845 में प्रतिवादी-कर्मचारी ने अपने लिखित बयान के पैरा 8 में तर्क दिया था कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश 4 अक्टूबर, 1985 को तथाकथित शासी निकाय द्वारा पारित किया गया था जो कानूनी इकाई नहीं थी और इसलिए, समाप्ति का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी कर्मचारी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के संदर्भ में उनके द्वारा दायर 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4383 में उनकी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को फिर से चुनौती देने से रोक दिया गया था क्योंकि उनकी सेवाओं की समाप्ति के

संबंध में मामला सीधे और काफी हद तक मुद्दे में था। प्रबंधन द्वारा दायर 1987 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2845 और प्रतिवादी द्वारा दायर 1988 का एलपीए नंबर 25। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे पी.के.विगायन बनाम कमलाक्षी अम्मा, एआईआर 1994, एस.सी. 2145 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से पूर्ण समर्थन मिलता है।

(पैरा 11)

आगे यह यह निर्धारित किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में त्रुटि की कि प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा उसकी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर 1987 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4383 को पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं किया गया था और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 4 अक्टूबर, 1985 के समाप्ति आदेश को रद्द करना टिकाऊ नहीं है।

(पैरा 12)

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226/227-हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979-धारा 7/ए-निलंबन- अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि कर्मचारी को छह महीने की अवधि से अधिक निलंबित रखा जाना है, एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत की जानी है जिसमें निलंबन अवधि बढ़ाने के कारणों को निर्दिष्ट करना है - रिपोर्ट छह महीने की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक महीने पहले प्रस्तुत की जानी है - निदेशक, उच्च शिक्षा की ऐसी मंजूरी नहीं मांगी गई है - कर्मचारी इसके हकदार हैं छह महीने की अवधि को छोड़कर निलंबन की अवधि के लिए लाभ।

(पैरा 13)

प्रतिवादी-कर्मचारी की इस दलील के संबंध में कि वह निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार था क्योंकि प्रबंधन को उसे निलंबित करने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक नियम नहीं था, यह माना गया कि धारा 7-ए के संदर्भ में, यदि किसी संबद्ध कॉलेज की प्रबंध समिति किसी कर्मचारी को छह महीने की अवधि से अधिक समय तक निलंबित रखना उचित समझती है, तो उसे कम से कम एक महीने पहले निदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। छह महीने की अवधि की समाप्ति, जिसमें निलंबन अवधि को बढ़ाने के कारणों को निर्दिष्ट किया गया हो। रिकॉर्ड से, हमें यह नहीं पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्रबंध समिति द्वारा छह महीने की अवधि समाप्त होने से एक महीने पहले निदेशक, उच्च शिक्षा को भेजी गई थी और निदेशक, उच्च शिक्षा की मंजूरी नहीं ली गई थी। निर्दिष्ट अवधि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-कर्मचारी 14 नवंबर, 1981 से छह महीने की अवधि को छोड़कर निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन का हकदार होगा, जिस तारीख को उसे प्रबंधन द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

(पैरा 14)

एस. सी. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता और आशीष कपूर, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से ।

प्रतिवादी संख्या 1 व्यक्तिगत रूप से, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

सतपाल, जे.

(1) यह अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22 सितंबर, 1993 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-समाज के इस तर्क को खारिज कर दिया कि रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) ने अपने निलंबन के संबंध में 14 नवंबर, 1981 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी और उनकी सेवाओं की समाप्ति के संबंध में 4 अक्टूबर, 1987 के आदेश को रचनात्मक पुनर्न्याय के सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, और उपरोक्त आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि ये ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए थे जो ऐसा करने में सक्षम नहीं थे।

(2) संक्षेप में कहा गया है, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-सोसाइटी एक निजी कॉलेज चलाती है, जिसका नाम है श्री लाई नाथ हिंदू कॉलेज, रोहतक, और प्रतिवादी प्रासंगिक समय में उक्त कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम कर रहा था। अपीलकर्ता ने कदाचार के कुछ कृत्यों के लिए प्रतिवादी को आरोप-पत्र जारी किया और जांच करने के बाद, सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा और हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 7 के तहत आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को रिकॉर्ड के साथ उच्च शिक्षा निदेशक, हरियाणा को भेजा गया। निदेशक ने अपने पत्र, दिनांक 18 मई, 1983 के माध्यम से, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रक्रियात्मक कमजोरियों से ग्रस्त थी। उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की, और उक्त अपील को राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर, 1983 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। उपरोक्त आदेश को अपीलकर्ता ने सी.डब्ल्यू.पी. में चुनौती दी थी। इस न्यायालय में 1984 का क्रमांक 387. इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले, दिनांक 6 सितंबर 1984 (*हिंदू एजुकेशन सोसाइटी (पंजीकृत) बनाम हरियाणा राज्य, और अन्य*[1] के रूप में रिपोर्ट किया) ने रिट याचिका को अनुमति दी, 18 मई, 1983 और 26 अक्टूबर, 1983 के उपरोक्त आदेशों को रद्द करते हुए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए मामले को निदेशक को भेज दिया गया। उक्त निर्णय का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है: -

"इस प्रकार मामले को उसे सौंपने पर अधिनियम की धारा 7(4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, वह अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार करेगा कि क्या उसे प्रस्तावित दंड को मंजूरी देनी चाहिए या इसे नियमों के तहत अनुमत सीमा तक कम करना चाहिए।"

---

[1] 1984 (3) S.L.R. 717.

पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 10 अक्टूबर, 1984 को निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त फैसले को प्रतिवादी द्वारा एल.पी.ए. संख्या 1132/1984 में चुनौती दी गई थी, जिसे 11 मार्च 1985 को खारिज कर दिया गया था।

(3) पक्षों को सुनने के बाद, निदेशक, उच्च शिक्षा ने अपीलकर्ता के प्रस्ताव को अपने आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1985 द्वारा स्वीकार कर लिया, लेकिन सेवा से बर्खास्तगी के दंड को सेवाओं की साधारण समाप्ति में बदल दिया। निदेशक द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"परिणामस्वरूप, मेरे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि प्रबंधन को श्री पसरीजा से छुटकारा पाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, हालांकि श्री पसरीजा का आचरण "बहुत ही निंदनीय है और किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। मुझे लगता है कि उन पर बर्खास्तगी का दंड लगाना काफी कठोर होगा जो उन्हें भविष्य के रोजगार से भी वंचित कर देगा। तदनुसार, मैं प्रबंधन के प्रस्ताव को इस हद तक स्वीकार करता हूं कि श्री एस.एस. पसरीजा पर सेवाओं की समाप्ति का दंड लगाया जा सकता है, इस आशा के साथ कि वह सबक सीखेंगे और जो नौकरी उन्हें मिल सकती है, उसमें काम और आचरण में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अन्यत्र।"

(4) निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 सितंबर, 1985 के अनुसरण में, अपीलकर्ता-प्रबंधन ने 4 अक्टूबर, 1985 को समाप्ति का औपचारिक आदेश पारित किया। दिनांक 5 सितंबर, 1985 को पारित आदेश से व्यथित होकर निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिस पर विचार किया गया और स्वीकार कर लिया गया, - विस्तृत आदेश, दिनांक 6 अप्रैल, 1987, श्रीमती द्वारा पारित। -शारदा रानी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हरियाणा। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"मैंने अपनी इच्छा से श्री सुभाष कपूर और प्रिंसिपल डॉ. एस.आर. मदन से पूछताछ की क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ 1973 से 1981 तक आचरण और कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत थी, जब उसके खिलाफ वर्तमान मामला शुरू किया गया था। वे मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं ला सके जिससे यह पता चल सके कि वर्तमान कार्यवाही से पहले इन लंबे वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता का आचरण अशोभनीय था। इस स्तर पर, श्री बाली ने कहा कि विवाद की जड़ तब शुरू हुई जब याचिकाकर्ता ने अपना वेतन प्राप्त किए बिना वेतन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उपरोक्त दर्ज कारणों से, संशोधन स्वीकार किया जाता है, निदेशक के दिनांक 5 सितंबर, 1985 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और शासी निकाय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सभी लाभों और सेवा की निरंतरता के साथ सेवा में बहाल किया जाए।*'

(5) अपीलकर्ता-प्रबंधन ने 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 में शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश, दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को चुनौती दी। उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी, - निर्णय, दिनांक 1 सितंबर, 1987 द्वारा। इस निर्णय के द्वारा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को रद्द कर दिया गया, और निदेशक, उच्च

शिक्षा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1985 को रद्द कर दिया गया। , हरियाणा, बहाल कर दिया गया।

(6) प्रतिवादी व्याख्याता ने 1 सितंबर 1987 के उक्त फैसले को 1988 के एल.पी.ए नंबर 25 में चुनौती दी, जिसे इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 17 जनवरी 1990 के फैसले के तहत खारिज कर दिया था। यहां यह बताया जा सकता है कि प्रतिवादी ने 19 जनवरी, 1991 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ 1991 के सी.एम. नंबर 1044 के तहत एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसे एक डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया था।

(7) 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 2845 के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 6 अप्रैल, 1987 के खिलाफ दायर की गई थी। प्रतिवादी कर्मचारी ने 20 जुलाई, 1987 को एक रिट याचिका संख्या सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4388/1987 भी दायर की। अपीलकर्ता प्रबंधन द्वारा पारित निलंबन आदेश दिनांक 14 नवंबर, 1981 और आदेश 13 सितंबर, 1982 और समाप्ति आदेश, दिनांक 4 अक्टूबर, 1985 को रद्द करना। इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय, दिनांक 22 सितंबर, 1993 द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उपरोक्त आदेशों, दिनांक 14 नवंबर, 1981, 13 सितंबर, 1982 और 4 अक्टूबर, 1985 को रद्द कर दिया, और प्रबंधन को प्रतिवादी-कर्मचारी को पिछले वेतन और परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता प्रबंधन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस रिट याचिका में उठाए गए बिंदु इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पहले ही तय किए जा चुके हैं, - 1988 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 25 में 17 जनवरी, 1990 के फैसले के तहत, और इस प्रकार इस रिट याचिका को पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा रोक दिया गया था, 22 सितंबर, 1991 के इस निर्णय से व्यथित होकर प्रबंधन द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

(8) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपूर ने प्रस्तुत किया कि 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 में, अपीलकर्ता-प्रबंधन ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को चुनौती दी थी। जिसके द्वारा मंत्री ने निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1985 को रद्द कर दिया था और उन्हें सभी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी ने अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से तर्क दिया था कि 4 अक्टूबर, 1985 को पारित उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश कानूनी नहीं था क्योंकि तथाकथित शासी निकाय आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद, 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 को स्वीकार कर लिया और मंत्री द्वारा पारित 6 अप्रैल, 1987 के आदेश को रद्द कर दिया और निदेशक द्वारा पारित 5 सितंबर, 1985 के आदेश को बहाल कर दिया। , उच्च शिक्षा, जिसके संदर्भ में प्रबंधन के प्रस्ताव को कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का जुर्माना लगाने की सीमा तक स्वीकार कर लिया गया था और उसके बाद 4 अक्टूबर, 1985 को प्रबंधन द्वारा औपचारिक समाप्ति आदेश जारी किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय को कर्मचारी द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 25/1988 में डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी-कर्मचारी उनके द्वारा दायर 1987 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 4383 में समाप्ति के आदेश को फिर से चुनौती नहीं दे सकता है, और विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की कि उक्त रिट याचिका पुनर्न्याय सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं थी।

(9) प्रतिवादी नंबर 1, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, ने प्रस्तुत किया कि प्रबंधन द्वारा दायर 1987 की पिछली रिट याचिका संख्या 2845 में, मुद्दा उसकी सेवाओं की समाप्ति के संबंध में प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का था, लेकिन प्रबंधन द्वारा पारित समाप्ति का औपचारिक आदेश, दिनांक 4 अक्टूबर, 1985, उस रिट याचिका का विषय नहीं था और उनके द्वारा दायर रिट याचिका, सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4383/1987 में, उन्होंने 4 अक्टूबर, 1985 के समाप्ति के औपचारिक आदेश को चुनौती दी थी, और इसके अलावा, उन्होंने 14 नवंबर, 1981 और 13 सितंबर, 1982 के निलंबन आदेश को भी चुनौती दी थी। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व न्यायिक सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि पुनर्न्याय का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने *अमलगेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड अन्य बनाम जनपद सभा छिंदवाड़ा और अन्य*[2], *ईशर सिंह बनाम सरवन सिंह और अन्य*[3], में सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों पर भरोसा जताया। और *नरेश चंद एडवोकेट, पटियाला बनाम पंजाब राज्य बिजली बोर्ड*[4] में इस न्यायालय का एक निर्णय उन्होंने आगे कहा कि केवल एक प्रश्न उठाना पुनर्न्याय सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है। इस दलील के समर्थन में, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसे *सीता और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य* [5]के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

(10) प्रतिवादी नंबर 1 ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि समाप्ति का आदेश, दिनांक 4 अक्टूबर, 1985 सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था, वह अवैध और अमान्य था। उन्होंने आगे कहा कि नियुक्ति पत्र में प्रबंधन को निलंबित करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई खंड नहीं था और न ही इस संबंध में कोई वैधानिक नियम था और इस प्रकार वह निलंबन के तहत रहने की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के बजाय पूर्ण वेतन के हकदार थे। इस दलील के समर्थन में, उन्होंने *मोहम्मद किफायतुल्ला बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट*[6] मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। और जोनल *मैनेजर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम खलील अहमद सिद्दीकी*[7] में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक निर्णय।

(11) हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, द्वारा की गई दलीलों पर उत्सुकता से विचार किया है। जैसा कि पहले कहा गया है, निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ ने अपने आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1985 द्वारा, 'प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करने का जुर्माना लगाने' की सीमा तक प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संशोधन में उक्त आदेश को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अपने आदेश, दिनांक 6 अप्रैल 19एस7 द्वारा रद्द कर दिया था, और प्रतिवादी को सभी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, प्रबंधन ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा 1987 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 2845 में पारित 6 अप्रैल, 1987 के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी, जिसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी थी, - निर्णय, दिनांक 1 सितंबर, 1987 और तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को रद्द कर दिया गया, और निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 5

---

[2] A.I.R. 1964 S.C. 1013,
[3] A.I.R. 1965 S.C. 948.
[4] 1993 (1) P.L.R. 355
[5] A.I.R, 1969 All. 342
[6] 1980 (3) S.L.R. 295.
[7] 1982 Labour Industrial Cases 1140.

सितंबर, 1985 को बहाल कर दिया गया। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति 'सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845/1987 में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा था। 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 के फैसले को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था, - 1988 के एल.पी.ए. संख्या 25 में 17 जनवरी, 1990 के फैसले के जरिए। उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा पारित समाप्ति के आदेश को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सही ढंग से रद्द कर दिया था। 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 में प्रतिवादी-कर्मचारी ने अपने लिखित बयान के पैरा 8 में तर्क दिया था कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश 4 अक्टूबर, 1985 को तथाकथित शासी निकाय द्वारा पारित किया गया था जो कानूनी इकाई नहीं थी और इसलिए, समाप्ति का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, प्रतिवादी कर्मचारी को उसकी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को फिर से 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4383 में चुनौती देने से रोक दिया गया था, जो कि उसकी सेवाओं की समाप्ति के संबंध में नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के संदर्भ में उसके द्वारा दायर किया गया था। प्रतिवादी, 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2845 में प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से मुद्दा था। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे *पी.के. विगयोम बनाम कमलाक्षी ऐरन्ना*[8] में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से पूरा समर्थन मिलता है।

(12) इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा उसकी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को चुनौती देने वाली 1987 की सी.डब्ल्यू.पी संख्या 4383 को मानने में त्रुटि की है। पूर्व न्यायिक सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं किया गया था, और इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 4 अक्टूबर, 1985 को समाप्ति के आदेश को रद्द करने वाला आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है।

(13) प्रतिवादी-कर्मचारी के इस तर्क के संबंध में कि वह निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन का हकदार था क्योंकि प्रबंधन को उसे निलंबित करने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक नियम नहीं था, अधिनियम के धारा 7-ए का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"7ए. छह महीने से अधिक समय तक निलंबन जारी रखना.—(1) यदि किसी संबद्ध कॉलेज की प्रबंध समिति किसी कर्मचारी को छह महीने की अवधि से अधिक समय तक निलंबित रखना उचित समझती है, तो वह छह महीने की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक महीने पहले निदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें कर्मचारी की निलंबन अवधि को छह महीने से अधिक बढ़ाने के कारणों को निर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपधारा (1) के तहत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निदेशक एक आदेश पारित करेगा कि विस्तार दिया जाए या नहीं। विस्तार देने से इनकार करने की स्थिति में, प्रबंध समिति आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर कर्मचारी को बहाल कर देगी, ऐसा न करने पर संबंधित कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर बहाल किया गया माना जाएगा। "

[8] A.I.R. 1994 S.C. 2145.

(14) धारा 7ए के संदर्भ में, यदि किसी संबद्ध कॉलेज की प्रबंध समिति इसे समीचीन समझती है किसी कर्मचारी को छह महीने की अवधि से अधिक समय तक निलंबित रखने के लिए, छह महीने की अवधि की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले निदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें निलंबन अवधि के विस्तार के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा। रिकॉर्ड से, हमें यह नहीं पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्रबंध समिति द्वारा छह महीने की अवधि समाप्त होने से एक महीने पहले निदेशक, उच्च शिक्षा को भेजी गई थी। निर्धारित अवधि में निदेशक, उच्च शिक्षा का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-कर्मचारी 14 नवंबर, 1981 से छह महीने की अवधि को छोड़कर निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन का हकदार होगा, जिस तारीख को उसे प्रबंधन द्वारा निलंबित कर दिया गया था। यहां यह बताया जा सकता है कि यह बिंदु 1987 की पिछली रिट याचिका संख्या 2845 का विषय नहीं था, जो प्रबंधन द्वारा दायर की गई थी। चूंकि निलंबन उस रिट याचिका का विषय नहीं था, इसलिए निलंबन आदेशों को चुनौती के संबंध में पूर्व न्यायिक सिद्धांत लागू नहीं होता है।

(15) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है प्रबंधन की अपील को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4383/1987 में प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सके। हालाँकि, प्रतिवादी-कर्मचारी ऊपर बताए अनुसार छह महीने की अवधि को छोड़कर निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार होगा और अपीलकर्ता-प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी नंबर 1 को पूर्ण वेतन का भुगतान करे। ऊपर बताए अनुसार निलंबन की अवधि के संबंध में, उसे पहले से भुगतान की गई जीवन निर्वाह भत्ता की राशि की कटौती के बाद, इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh